ताकि सनद रहे

नए नियम समझिए और फिर किरायेदार बनिए !

भारत में घर किराये पर लेने का मतलब होता था अनौपचारिक नियमों, असंगत समझौतों और अचानक आए झटकों से निपटना, लेकिन अब किराये के नियमों में एक बड़ा बदलाव आने वाला है।

सरकार ने New Rent Agreement 2025 को लागू कर दिया है। इसका मकसद किराये के कॉन्ट्रैक्ट को आसान बनाना, मकान मालिक और किरायेदार के बीच के झगड़ों को कम करना और इस अनौपचारिक, लेकिन तेजी से बढ़ते मार्केट में एक जैसे नियम लागू करना है।

डिजिटल स्टाम्प अब अनिवार्य

इस सुधार का सबसे अहम हिस्सा यह है कि अब सभी किराये के समझौतों (रेंट एग्रीमेंट) को हस्ताक्षर करने की तारीख से दो महीने के अंदर डिजिटल स्टाम्प कराना जरूरी होगा।

- ऐसा न करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। यह नियम उन मौखिक या बिना रजिस्टर्ड समझौतों को कम करेगा, जिनके कारण अक्सर कानूनी झगड़े होते हैं।

सिक्योरिटी डिपॉजिट सीमित

सिक्योरिटी डिपॉजिट की सीमा तय की गई है, जो बड़े शहरों में किरायेदारों के लिए हमेशा ही एक बड़ी परेशानी रही है।

- नए नियमों के तहत, रिहायशी संपत्तियों के लिए डिपॉजिट की सीमा सिर्फ दो महीने के किराये तक सीमित होगी। पहले यह छह से 10 महीने के किराये के बराबर होती थी। यह किरायेदारों के लिए बहुत बड़ी राहत है और वैश्विक किरायेदारी मानकों की ओर एक कदम है।

किराये में वृद्धि की मनमानी नहीं

किराये में संशोधन या वृद्धि अब साल में सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है, और इसके लिए मकान मालिकों को 90 दिन का नोटिस देना जरूरी होगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अचानक साल के बीच में होने वाली बढ़ोतरी के झटके से सुरक्षा मिलेगी।

- **डिजिटल भुगतान को बढ़ावा**...5,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक का कोई भी किराया डिजिटल रूप से (यूपीआई, बैंक ट्रांसफर) ही देना होगा। यह दोनों पक्षों को सुरक्षा प्रदान करेगा और एक स्वच्छ डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा।

स्टैंडर्ड रेंट एग्रीमेंट...ऊंचे किराये पर टीडीएस

एक समान किराये समझौता प्रारूप (Uniform Rental Agreement Format) जारी। समझौते में कोई छिपी हुई लाइनें, कोई अजीब क्लॉज या कोई अतिरिक्त नियम नहीं होगा। सब कुछ स्पष्ट तौर पर लिखा होगा।

- 50,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक किराये पर टीडीएस लगेगा। यह नियम प्रीमियम सेगमेंट को मौजूदा टैक्स नियमों के दायरे में लाएगा और भविष्य में कर विभाग के साथ होने वाले विवादों से बचाएगा।

इन सुधारों का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा...डिपॉजिट की सीमा तय होने, डिजिटल भुगतान अनिवार्य बनने और समझौतों के मानकीकृत होने से लाखों लोगों के लिए घर किराये पर लेना अधिक सुलभ होगा और विवाद भी कम होंगे।
- गौतम प्रसाद, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट

तारीख पता है?

आईपीओ लिस्टिंग
- **10 दिसंबर :** मीशो (5,421 करोड़ रुपये), एकस लिमिटेड (921 करोड़ रुपये), विद्या वायर्स (300 करोड़ रुपये)
- **15 दिसंबर :** वेकफिट इनोवेशंस (1,288 करोड़ रुपये)

घोषणा
- **12 दिसंबर :** सीपीआई और डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति

डिस्क्लेमर : अपना पैसा में छपे विचार, राय और निवेश संबंधी सुझाव अलग-अलग विशेषज्ञों, ब्रोकर फर्मों या रिसर्च संस्थानों के हैं। इनसे अखबार या उसके प्रबंधन की सहमति जरूरी नहीं है। कृपया किसी भी तरह का निवेश फैसला लेने से पहले अपने पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। इस जानकारी के आधार पर होने वाले किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी अखबार या उसके प्रबंधन की नहीं होगी।

जब शेयर बाजार तेजी से करवट लेता है, तो अनुभवी फंड मैनेजर भी बाजार को मात देने में पसीना छोड़ देते हैं, दिन भर में उलट-पलट होते बाजार में म्यूचुअल फंड निवेशक एक बड़ा बदलाव ला रहे हैं।

पैसिव फंड : अस्थिर बाजार के सितारे

पैसिव फंड में इंडेक्स फंड, ईटीएफ (गोल्ड, सिल्वर व अन्य) और विदेशी एक्सचेंज जैसे हैंगसेंग, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में निवेश के लिए फंड ऑफ फंड्स (ओवरसीज) शामिल हैं। कम खर्च, आसान निवेश और स्थिर लॉन्ग-टर्म रिटर्न की वजह से ये फंड तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं।

म्यूचुअल फंड में निवेशक के नियम बदल रहे हैं। पुराना नियम था, तेज उतार-चढ़ाव में जानकार या फंड मैनेजर का हाथ थामो, यानी एक्टिव फंड पर दांव लगाओ, जिसे कोई विशेषज्ञ संभालता है। मगर अब पिछले एक साल के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि निवेशक सक्रिय (एक्टिव) फंड्स के बजाय तेजी से निष्क्रिय (पैसिव) फंड्स पर भरोसा कर रहे हैं।

AMFI के मुताबिक, पैसिव फंड फोलियो अक्तूबर, 2025 तक 3 गुना से ज्यादा बढ़कर 4.81 करोड़ हो गए। अक्तूबर, 2024 में यह 1.30 करोड़ था। इसके मुकाबले एक्टिव फंड (ओपन एंडेड 10 व इक्विटी 16.5 फीसदी) में फोलियो की वृद्धि दर आधी है।

■ क्यों बढ़ रहे हैं पैसिव फंड के कद्रदान?

भारतीय निवेशकों ने अपने तजुर्बे से सीख लिया है कि बाजार में अनिश्चितता होती है, तो ज्यादा फीस देकर किसी फंड मैनेजर के पूर्वाग्रह या गलत फैसलों पर निर्भर रहने से बेहतर है कि कम लागत वाले पैसिव फंड को अपनाया जाए।

निवेशकों की बदलती पसंद के कारण पिछले एक साल में एक्टिव फंड की तुलना में पैसिव फंड में सबसे ज्यादा नई स्कीमें लॉन्च हुई हैं...

पैरामीटर	अक्तू.25	अक्तू.24	वृद्धि
ओपन एंडेड स्कीम	329	315	14%
ग्रोथ/इक्विटी स्कीम	539	471	68%
पैसिव फंड स्कीम	546	687	141%

स्रोत AMFI

■ क्या होते हैं पैसिव फंड?

ऐसे फंड, जो किसी बाजार इंडेक्स (जैसे Nifty 50, Nifty Next 50, Nifty Midcap 150, और Nifty Smallcap 250) को ट्रैक करते हैं। इसका मकसद बाजार के प्रदर्शन को कॉपी करना होता है। ये सक्रिय रूप से स्टॉक चुनने के बजाय, इंडेक्स में शामिल शेयरों को उसी अनुपात में खरीदते हैं, ताकि उसकी चाल और रिटर्न बिल्कुल इंडेक्स जैसे रहें। इसे ट्रैकिंग कहते हैं।

रिटर्न के मामले में एक्टिव से आगे पैसिव

सक्रिय फंड्स	01 वर्ष रिटर्न	पैसिव फंड्स	01 वर्ष रिटर्न
HDFC ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक फंड	24.32%	MOSL निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड	32.95%
DSP क्रेडिट रिस्क फंड	22.55%	ABSL निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड	32.18%
DSP मल्टी एसेट अलोकेशन फंड	20.80%	टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड	27.47%
DSP बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेस फंड	20.08%	कोटक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेस इंडेक्स फंड	25.93%
HDFC डिफेंस फंड	19.88%	MOSL BSE फाइनेंशियल एक्स-बैंक 30 इंडेक्स फंड	20.38%

स्रोत-वैल्यू रिसर्च

■ ईटीएफ ने चमकाया बाजार

एक्टिव के बजाय पैसिव फंड में निवेश बढ़ने की एक वजह गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ का आकर्षक रिटर्न भी है। गोल्ड ईटीएफ ने 51% और सिल्वर ईटीएफ ने 53% का रिटर्न दिया है।

अक्तूबर 2025 के दौरान पैसिव फंड में आए कुल निवेश 16,668 करोड़ रुपये में से सबसे ज्यादा 7,743 करोड़ रुपये का निवेश अकेले गोल्ड ईटीएफ में हुआ है। इसके बाद 6,181 करोड़ रुपये का निवेश अन्य ईटीएफ में गया।

■ पैसिव फंड के फायदे

- बाजार, फंड मैनेजर या तिमाही नतीजों पर नजर रखने की जरूरत नहीं।
- खर्च एक्टिव फंड्स से कम (0.1%–0.6%), जिससे शुद्ध रिटर्न बढ़ता है।
- आपको हमेशा पता होता है कि आपके फंड में कौन-सी कंपनियां हैं।
- लंबी अवधि में, इंडेक्स फंड्स ने अधिकांश एक्टिव फंड्स से अधिक रिटर्न दिया है।

■ कुछ नुकसान भी हैं-

- इंडेक्स के रिटर्न से तो मेल खाएंगे, लेकिन उसे कभी भी हरा नहीं पाएंगे।
- अगर बाजार 20% गिरता है, तो इंडेक्स फंड भी 20% ही गिरेगा। इनके पास छिपने की कोई जगह नहीं होती।
- बाजार में तनाव के दौरान फंड मैनेजर होल्डिंग्स बदल नहीं सकते।
- कुछ फंड इंडेक्स से भटक सकते हैं।

जोखिम के बीच संतुलित कदम

कम लागत, अधिक पारदर्शिता और बाजार के औसत रिटर्न के साथ सुरक्षित रूप से निवेश शुरू करने वालों के लिए इंडेक्स फंड अच्छा एंट्री प्वाइंट है। निवेशक अब अनुशासन, पारदर्शिता और कम लागत को प्राथमिकता दे रहे हैं। वह जान गए हैं कि बाजार को हराने की कोशिश करने से बेहतर है कि बाजार के साथ चला जाए।

मेजर आशीष चड्ढा (रि.)
सीईओ, चड्ढा इनवेस्टमेंट कंसल्टेंट प्रा. लि.

पैसिव फंड कब खरीदें?

- उनके लिए अच्छा विकल्प, जो लंबी अवधि के शांत निवेश को चुनते हैं
- शुरुआती निवेशकों के लिए आदर्श।
- 15-20 वर्ष की लंबी अवधि में ये सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं।
- जब बाजार गिरता है, तो एकमुश्त निवेश फायदेमंद हो सकता है।

कब बेचें?

- जब अपने वित्तीय लक्ष्य तक पहुंच जाएं- जैसे घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा।
- जब आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी ज्यादा हो जाए। रिबैलेंस की जरूरत हो।
- 1-2 साल में पैसों की जरूरत हो, तब सुरक्षित डेट फंड में शिफ्ट हो जाएं।
- आपको लगता है कि कोई सेक्टर इंडेक्स बहुत ज्यादा जोखिम भरा है।

कितना निवेश सही...

- **रूढ़िवादी :** 10-15% सिर्फ सादे इंडेक्स फंड्स में, शेष डेट, फिक्स्ड इनकम में।
- **मध्यम :** 10-15% सादे इंडेक्स फंड में, 5% सेक्टोरल इंडेक्स फंड (एक्टिव फंड या अंतरराष्ट्रीय फंड के साथ)।
- **आक्रामक :** 10-15% इंडेक्स फंड, 10-15% सेक्टोरल इंडेक्स फंड (निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, मिडकैप का मिश्रण)।

समझ-बूझ

म्यूचुअल फंड उपहार में देना हुआ आसान

अब आप अपने म्यूचुअल फंड्स यूनिट को और भी आसानी से उपहार में दे सकते हैं। SEBI ने डीमैट खाते की तरह अब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट (SOA) आधारित यूनिट्स को उपहार में देने की प्रक्रिया को सरल बनाकर लाखों निवेशकों के लिए बड़ी टैक्स बचत का रास्ता खोल दिया है।

SOA में म्यूचुअल फंड कंपनी एक पेपर या ई-मेल पर हिसाब की कॉपी देती है। इनकी यूनिट डिजिटल रूप से उपलब्ध नहीं होती है।

- अब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट (SOA) आधारित यूनिट्स को भी सीधे ट्रांसफर किया जा सकेगा।
- पहले, डायरेक्ट ट्रांसफर की अनुमति नहीं थी।
- उपहार में देने के लिए इन यूनिट्स को बेचना पड़ता था, जिससे एग्जिट लोड और पूंजीगत लाभ कर लगता था।
- उच्च टैक्स स्लैब वाले निवेशक भारी मुनाफे वाली यूनिट्स को ऐसे परिवार के वयस्क सदस्य को गिफ्ट दे सकते हैं, जिसकी आय शून्य या कम हो।
- अब यूनिट्स को भुनाए बिना, केवल एक लिंक और दो ओटीपी के माध्यम से तुरंत उपहार में दिया जा सकेगा।

खबरों के आर-पार

BSBD अकाउंट की सुविधाओं में विस्तार

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने BSBD (बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट) खाताधारकों को मिलने वाली सुविधाओं में वृद्धि की है

- 01 अप्रैल से सभी बैंकों को इन खातों में पूरी तरह से मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग सुविधा देना अनिवार्य होगा।
- इन खातों में ब्रांच, एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के जरिये कैश जमा करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।
- BSBD खाता खोलने के लिए कोई आय या प्रोफाइल आधारित पात्रता शर्त नहीं।
- अगर कोई पुराना BSBD खाताधारक मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग या फ्री कैश डिपॉजिट सुविधा चाहता है, तो बैंक को ये सुविधाएं तुरंत देनी होंगी।

पूछताछ

मैं कैसे इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक कर सकता हूं?

कई करदाताओं के लिए विभिन्न कारणों से इनकम टैक्स रिफंड में सामान्य से अधिक समय लग रहा है। ऐसे करदाता अपने रिफंड की स्थिति ऑनलाइन जांच सकते हैं।

- www.incometax.gov.in पर जाएं। 'लॉग इन' पर क्लिक करें। PAN और पासवर्ड डालें।
- होम पेज के टास्कबार पर ई-फाइल> आयकर रिटर्न> फाइल किए गए रिटर्न देखें पर क्लिक करें।

- करदाता द्वारा फाइल किए गए आयकर रिटर्न की आकलन वर्ष के अनुसार एक पूरी टाइमलाइन दिखेगी।
- यहां पर आपको रिफंड की वर्तमान स्थिति दिखाई देगी।

■ मैं रिवाइज्ड रिटर्न कब तक फाइल कर सकता हूं?

आप जिस आकलन वर्ष (Assessment Year) के लिए रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उसकी समाप्ति से पहले या आकलन वर्ष की समाप्ति के 31 दिसंबर तक (जो भी पहले हो) रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उदाहरण से समझिए, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए (जिसका आकलन वर्ष 2025-26 है), रिवाइज्ड रिटर्न की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2026 होगी।

फंड की फिटनेस

NFO की जानकारी

- **अवधि :** 02 दिसंबर से 10 दिसंबर
- **प्रकार :** ओपन-एंडेड स्कीम, जो BSE 500 डिविडेंड लीडर्स 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करेगी
- **फंड मैनेजर :** एकता गाला, रितेश पटेल
- **न्यूनतम निवेश :** 5,000 रुपये
- **जोखिम :** बहुत ज्यादा

सिंगल निवेश में डबल मुनाफा

डिविडेंड स्टॉक्स से डबल फायदा, कीमत वृद्धि और नियमित लाभांश आय

निवेशकों को स्थिर व नियमित आय के साथ लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन की क्षमता प्रदान करने के लिए मिराए एसेट म्यूचुअल फंड (Mirae Asset Mutual Funds) ने एक नया ETF (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) पेश किया है। इसका नाम मिराए एसेट बीएसई 500 डिविडेंड लीडर्स 50 ईटीएफ है।

Mirae Asset BSE 500 Dividend Leaders 50 ETF

यह स्कीम उन कंपनियों में निवेश का अवसर देगी, जो लंबे समय से लगातार डिविडेंड देती आ रही हैं। इन कंपनियों की बैलेंस शीट मजबूत होती है और उनके पास अच्छा कैश फ्लो भी होता है। डिविडेंड पेआउट कंपनियों की बिजनेस क्वालिटी और मजबूती को दर्शाता है।

लगातार डिविडेंड देने वाली कंपनियों को मजबूत गवर्नेंस और वित्तीय अनुशासन वाला माना जाता है। इस नई स्कीम से निवेशकों को हाई क्वालिटी वाली कंपनियों में निवेश करने का मौका मिलेगा, जिससे उन्हें स्थिर डिविडेंड और लंबी अवधि की ग्रोथ, दोनों का फायदा मिलेगा।

■ फंड का प्रदर्शन

डिविडेंड स्टॉक्स में निवेशकों को दो तरह से रिटर्न मिलता है। पहला स्टॉक की कीमत बढ़ने से और दूसरा डिविडेंड से नियमित आय के रूप में।

यह ETF BSE 500 Dividend Leaders 50 Index को ट्रैक करेगा। यह इंडेक्स BSE 500 की उन कंपनियों को चुनता है, जो लगातार डिविडेंड देती रही हैं। ETF केवल उन कंपनियों में निवेश करेगा, जिनकी लिस्टिंग कम से कम पांच साल पुरानी हो और जिन्होंने पिछले 10 साल में या लिस्टिंग से अब तक कम से कम 80 फीसदी बार डिविडेंड दिया हो।

■ क्या कहते हैं एक्सपर्ट

मनी ट्री के सह-संस्थापक सिद्धार्थ शर्मा कहते हैं कि जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा, तो इन फंड का प्रदर्शन भी बेहतर होगा। इसलिए, यह उन निवेशकों के लिए अच्छा है, जो मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं।

चाहिए कार की सेफ्टी, समग्र बीमा है जरूरी

कानूनी रूप से अनिवार्य थर्ड पार्टी बीमा की आधी-अधूरी सुरक्षा ने बढ़ाई कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस की मांग

पारस पसरिचा
हेड, मोटर इंश्योरेंस
पॉलिसीबाजार डॉट कॉम

रमेश ने जीएसटी रियायत का लाभ उठाकर नई कार खरीदी। जब बीमा लेने की बात आई, तब नियमों को पूरा करने के लिए, सिर्फ वही बीमा लिया, जो कानूनी रूप से अनिवार्य था-यानी सस्ता थर्ड पार्टी बीमा।

एक दिन रमेश की कार आगे चल रही दूसरी कार से टकरा गई। दोनों कार को अच्छा-खासा नुकसान हुआ।

रमेश की बीमा कंपनी ने दूसरी कार के नुकसान की भरपाई तो कर दी, लेकिन रमेश को अपनी कार की मरम्मत का खर्च खुद उठाना पड़ा।

भारत में ज्यादातर कार मालिक सालों से थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस लेते आए हैं, क्योंकि यह अनिवार्य और सस्ता है...लेकिन इसमें एक पेच है, यह केवल दूसरों को हुए नुकसान को ही कवर करता है, जिससे आपकी अपनी कार असुरक्षित रह जाती है।

सड़कों पर बढ़ते वाहनों, हर साल होने वाली लाखों दुर्घटनाओं, कारों की ऊंची कीमत, चोरी और तोड़-फोड़ के डर के अलावा हर साल जलवायु और प्राकृतिक आपदाओं के कारण अब नए कार मालिक कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस की ओर समझदारी से रुख कर रहे हैं, क्योंकि दुर्घटना, बाढ़ या चोरी जैसी अप्रत्याशित घटना में कोई भी अपनी जेब को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है।

थर्ड पार्टी बनाम समग्र (कॉम्प्रिहेंसिव) कार बीमा में अंतर

पैरामीटर	थर्ड पार्टी कार बीमा	कॉम्प्रिहेंसिव बीमा कवर
पॉलिसी कवरेज	बीमित वाहन के कारण थर्ड पार्टी की चोट, मृत्यु और संपत्ति नुकसान का कवर	थर्ड पार्टी की देनदारियों और बीमित कार को हुए नुकसान, दोनों का कवर
कानूनी मांग	भारतीय मोटर कानून के अनुसार अनिवार्य है	वैकल्पिक, अनिवार्य नहीं
मुख्य सीमाएं	बीमित कार के नुकसान को कवर नहीं करता है	थर्ड पार्टी कार बीमा से महंगा होता है
प्रीमियम	सस्ता, IRDAI कार इंजन क्षमता के आधार पर प्रीमियम तय करता है	थर्ड पार्टी से अधिक। कार के मेक और मॉडल, वाहन रजिस्ट्रेशन क्षेत्र और चुने गए राइडर्स पर आधारित होता है
ऐड-ऑन कवर	उपलब्ध नहीं	जीरो डेप, एनसीबी प्रोटेक्ट, रोडसाइड असिस्टेंस

■ 3+3 प्लान का नया ट्रेंड

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 01 सितंबर, 2018 से सभी नई कारों के लिए तीन साल का मल्टी-ईयर थर्ड पार्टी कार बीमा अनिवार्य है। थर्ड पार्टी बीमा के साथ ही अब मल्टी-ईयर ओन्ड डैमेज बीमा खरीदने का ट्रेंड रफ्तार पकड़ रहा है।

- मल्टी-ईयर कार इंश्योरेंस पॉलिसी से प्रीमियम में काफी बचत होती है।
- जब कोई ग्राहक तीन साल की पॉलिसी खरीदता है, तो प्रीमियम दर आज की कीमत पर लॉक हो जाती है।
- यह उन्हें महंगाई या बढ़ती मरम्मत लागत के कारण होने वाली वार्षिक प्रीमियम बढ़ोतरी से बचाता है।

इसे उदाहरण से समझते हैं:

- **एक साल के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस का प्रीमियम** =18,000 रुपये
- **03 साल तक रिन्यू कराया तो** = 54,000 रुपये
- **10% छूट के साथ प्रीमियम** = 48,600 रुपये
- **कुल बचत** = 5,400 रुपये

मल्टी-ईयर पॉलिसी पहली बार कार खरीदने वालों, रिस्क से बचने वालों और सुविधा व अनुपालन को प्राथमिकता देने वालों के लिए सबसे उपयुक्त है।

■ बीमा कंपनियों की तुलना करें

रिन्यूअल का मतलब यह नहीं है कि आपको उसी कंपनी के साथ रहना है। विभिन्न बीमाकर्ताओं की ऑनलाइन तुलना करें। केवल प्रीमियम नहीं, बल्कि उनकी क्लेम सेटलमेंट रेश्यो, ग्राहक सेवा, और कैशलेस गैराज का नेटवर्क भी देखें।

जानना जरूरी है

बीमा रिन्यूअल...रखें ध्यान

- **सही IDV (इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू) :** वह अधिकतम राशि, जिसका भुगतान बीमा कंपनी कार चोरी होने या पूर्ण क्षतिग्रस्त होने पर करेगी।
- **संतुलन बनाएं :** मूल्यह्रास के कारण हर साल IDV घटता है। सुनिश्चित करें कि आपका IDV न तो बहुत कम हो और न ही बहुत अधिक।
- **नो क्लेम बोनस का उपयोग करें :** यदि आपने पिछली पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं लिया, तो NCB के तहत प्रीमियम पर छूट मिलेगी।

IRDAI ने यूनिफॉर्म नो क्लेम बोनस (NCB) ग्रिड तैयार किया है, जिसके आधार पर आप मिलने वाली छूट का दावा कर सकते हैं:

- 01 वर्ष (पहला नवीनीकरण) : 20%
- 02 वर्ष (दूसरा नवीनीकरण) : 25%
- 03 वर्ष (तीसरा नवीनीकरण) : 35%
- 04 वर्ष (चौथा नवीनीकरण) : 45%
- 05 वर्ष (पांचवां नवीनीकरण) : 50%
- 05 वर्ष के बाद 50% पर बरकरार रहता है।

छोटे क्लेम से बचें...यदि मरम्मत का खर्च NCB छूट से कम है, तो क्लेम करने से बचें।
NCB ट्रांसफर...यदि बीमा कंपनी बदल रहे हैं, तो आपका NCB नई पॉलिसी में ट्रांसफर करें।

अपनी वर्तमान जरूरतों के आधार पर कवरेज और ऐड-ऑन की समीक्षा करें :

- **जीरो डेप्रिसिएशन :** नई या 05 साल तक की पुरानी कारों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है।
- **इंजन प्रोटेक्ट** ■ **रोडसाइड असिस्टेंस**

यदि आपकी कार बहुत पुरानी हो गई है या आपकी जरूरतें बदल गई हैं, तो उन ऐड-ऑन को हटा दें जिनकी अब आवश्यकता नहीं है।

इंफोग्राफिक्स

बदल रहा है सोने में निवेश का तरीका

सोना एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाने की राह पर है। तीन दिसंबर को दिल्ली में सोने का भाव 1,27,593 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। 17 अक्तूबर को सोने ने 1,30,874 रुपये का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया था।

31% घटी गोल्ड ज्वेलरी की मांग सितंबर में
20% बढ़ी सोने में इन्वेस्टमेंट डिमांड
86.2 टन हुई गोल्ड ईटीएफ होल्डिंग नवंबर, 2025
142 टन हुआ सोने का आयात अक्तूबर, 2025 में

सोने की फिजिकल मांग घटी...अब सोना सजने-संवरने के लिए नहीं, निवेश के लिए खरीदा जा रहा है।

कहां हो रहा है सोने में निवेश

मांग	जुलाई-सितंबर 2025	जुलाई-सितंबर 2024	अंतर %
ज्वेलरी डिमांड	88.8 टन	106.6 टन	-17
निवेश (बार, कॉइंस)	46.1 टन	43.1 टन	7
गोल्ड ईटीएफ	1,1808.74 करोड़ रुपये	4,181.72 करोड़ रुपये	182.38

स्रोत WGC , AMFI

कंटेंट : अमर उजाला बोनस टीम